# फिर टैरिफ का खतरा : अमेरिका ने भारत समेत 16 व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ शुरू की जांच

**कहा - अमेरिका अब अपने औद्योगिक आधार को उन देशों के लिए बलिदान नहीं करेगा, जो अतिरिक्त उत्पादन एवं क्षमता की अपनी समस्याएं हमारे यहां निर्यात कर रहे हैं**

**व्यापार अधिनियम की धारा 301 देती है अमेरिकी कंपनियों को क्षति पहुंचा रहे देशों पर एकतरफा टैरिफ बढ़ाने की शक्ति**

**इन देशों की जांच :** भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। अमेरिका ने इन देशों की सरकारों से परामर्श का आग्रह किया है।

■ इन जांचों पर टिप्पणियां 17 मार्च से दर्ज की जाएंगी। 15 अप्रैल तक आम लोगों और कंपनियों से सुझाव मांगे गए हैं। 5 मई के आसपास सार्वजनिक सुनवाई होगी।

**न्यूयॉर्क।** टैरिफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं। अब गलत तरीके से व्यापार करने का आरोप लगाते हुए ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ समेत 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ नई जांच शुरू की है।

यह जांच 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत की जा रही है, जो अमेरिका को उन देशों पर एकतरफा टैरिफ बढ़ाने की शक्ति देती है, जो उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहे हैं।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने कहा कि इन देशों की नीतियों, कार्यों तथा प्रथाओं की जांच शुरू की गई, जो विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता एवं अत्यधिक उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इसमें तय किया जाएगा कि इन देशों की नीतियां और प्रथाएं अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या नहीं और क्या वे अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालती हैं या उसे सीमित करती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अपने औद्योगिक आधार को उन देशों के लिए बलिदान नहीं करेगा, जो अतिरिक्त उत्पादन एवं क्षमता की अपनी समस्याएं हमारे यहां निर्यात कर रहे हैं। लक्ष्य यह है कि जुलाई में अस्थायी टैरिफ खत्म होने से पहले ही इस जांच के नतीजे और नए टैरिफ के प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ रद्द करने के बाद उठाया है। ट्रंप की टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए सैकड़ों अरब डॉलर के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए नए टैरिफ लगाने हेतु कई कानूनों का उपयोग कर रहे हैं। एजेंसी

# 200 से ज्यादा सांसद हटाना चाहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को

**नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किए जाने की संभावना**

**नई दिल्ली। ए।** मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सूत्र के अनुसार, लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किस सदन में पेश किया जाएगा। यह पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है।

विपक्ष के एक नेता ने बताया कि सांसदों ने नोटिस को लेकर काफी उत्साह दिखाया और आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बाद भी बृहस्पतिवार को कई सांसदों हस्ताक्षर किए। नियमों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

**इंडिया के सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर :** एक अन्य सूत्र के अनुसार, इस नोटिस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि पार्टी अब आधिकारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

**हटाने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी :** मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। महाभियोग केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है– सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

**मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए हैं सात आरोप**

एक उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार, नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सात आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 'पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण', 'चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना' और 'बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना' जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया है, खासकर मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई गई है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है।

## जेकेसीए घोटाला: फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

**श्रीनगर। ए।** एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया। श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने वारंट जारी किया, क्योंकि अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश नहीं हो सके। मजिस्ट्रेट ने अदालत में पेशी से छूट मांगने के अनुरोध संबंधी अब्दुल्ला की याचिका को भी खारिज कर दिया।

## खाड़ी संकट: शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गये

**इस्लामाबाद। ए।** पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बृहस्पतिवार को सऊदी अरब की संक्षिप्त सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते के कारण इस यात्रा में पाकिस्तान की भूमिका की परख होगी। दोनों देशों ने पिछले साल सितंबर में एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा दोनों ने किसी तीसरे देश द्वारा हमला किये जाने की स्थिति में एक-दूसरे की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जतायी थी। यह समझौता तब हुआ था जब इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं पर हमला किया था।

## जी-7 देशों का कड़ा फैसला, रूस पर जारी रहेंगे प्रतिबंध

**पेरिस। ए।** फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने स्पष्ट किया है कि जी-7 देशों ने मध्य पूर्व युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजारों में मची भारी उथल-पुथल के बावजूद रूस पर लगे प्रतिबंधों को कम करने या हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका-इस्राएल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गयी है, जिससे दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। अन्य जी-7 नेताओं के साथ एक वीडियो कॉल के बाद माक्रों ने कहा कि मौजूदा संकट किसी भी तरह से रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने को उचित नहीं ठहराता है।

## जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई 12 करोड़ की हेरोइन बरामद

**जम्मू। ए।** जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई करीब दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 101वीं बटालियन ने बुधवार देर रात बिश्नाह क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव में एक खेत से यह हेरोइन बरामद की।

## जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के पास वो शक्तियां नहीं: फारूक

**जम्मू। ए।** नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि चुनी हुई सरकार के पास वे अधिकार नहीं हैं, जो उसके पास होने चाहिए। अब्दुल्ला पर हुए हमले को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जा के अभाव के साथ जोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर नेकां अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव इस आश्वासन के साथ हुए थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

# ऊर्जा सुरक्षा पर शाह की अध्यक्षता में बनी कमेटी, केंद्र ने फिर कहा-गैस की कमी नहीं

**हरदीप पुरी ने लोकसभा में बताया, भारत के पास पर्याप्त गैस उत्पादन व आपूर्ति है | पश्चिम एशिया संघर्ष के लंबा चलने पर भी नहीं होगी परेशानी | तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से चल रहे, कभी-कभी 100% क्षमता से भी ज्यादा**

**संवाद न्यूज एजेंसी। नई दिल्ली।**

केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति पर निगरानी के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों की कमेटी गठित की है। कमेटी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हैं। कमेटी किसी भी संकट की स्थिति में आपात फैसले लेने, समाधान तलाशने के अलावा अन्य जरूरी उपाय करेगी। वहीं, केंद्र सरकार ने फिर कहा कि तेल और गैस की कोई कमी नहीं है।

हरदीप पुरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आए बड़े व्यवधान से देश सफलतापूर्वक निपट रहा है। यदि संघर्ष लंबा चला तब भी, भारत के पास पर्याप्त गैस उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था है। हर घर और उद्योग के लिए बिजली उत्पादन पूरी तरह से सुरक्षित है। पुरी ने कहा, संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए लगभग बंद है। इस मार्ग से वैश्विक कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के 20 प्रतिशत हिस्से की ढुलाई होती है। पुरी ने कहा, कच्चे तेल की भारत की आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। पहले हमारे आयात का 45% हिस्सा इसी प्रभावित मार्ग से होकर गुजरता था। संघर्ष शुरू होने से पहले ही हम अपने आयात का 55 फीसदी हिस्सा दूसरे मार्गों से ढोने लगे थे, जो अब बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है।

सरकार के दावों के बावजूद देशभर में एलपीजी की किल्लत दिख रही है। अहमदाबाद में एक गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए लोगों ने गाड़ी तक घेर लिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एजेंसी

## सीएनजी-पीएनजी की आपूर्ति 100 फीसदी, उद्योगों को 80 फीसदी

पुरी ने कहा, घरों में पाइप से आने वाली गैस और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की है। यह 100 फीसदी आपूर्ति जारी रहेगी। औद्योगिक व विनिर्माण उपभोक्ताओं को बीते छह महीनों के औसत के 80 प्रतिशत तक गैस मिलेगी। उर्वरक संयंत्रों को 70 प्रतिशत तक गैस मिलेगी, जिससे बुवाई के मौसम से पहले कृषि इनपुट श्रृंखला सुरक्षित रहेगी। रिफाइनरियां व पेट्रोकेमिकल इकाइयां नियंत्रित कटौती को सहन करेंगी और उस गैस को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

## शहरों में 25, गांवों में 45 दिन बाद सिलिंडर की बुकिंग

सरकार ने प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश के तहत एलपीजी के लिए प्राथमिकता आवंटन प्रणाली लागू की है। एलपीजी उत्पादन में 28% की वृद्धि हुई है। मांग नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद सिलिंडर बुकिंग का नियम लागू किया है। गांवों के लिए यह अवधि 45 दिन है। बुकिंग के ढाई दिन के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

■ *विकल्प के तौर पर एक माह के लिए कोयला, कैरोसीन व बायोमॉस के उपयोग की अनुमति दी गई है।*

## तेल टैंकरों को गुजरने देने पर जयशंकर ने अराघची से की बात

विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बृहस्पतिवार को बात कर होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय तेल जहाजों को गुजरने देने पर चर्चा की।

■ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों में ईरानी और हमारे विदेश मंत्री की तीन वार्ताएं हुई हैं। आखिरी वार्ता में जहाज की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई।

**होर्मुज के रास्ते कच्चे तेल के साथ जहाज मुंबई आया :** सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा लाइबेरिया के ध्वज वाला टैंकर शेनलॉन्ग स्वेजमैक्स मुंबई पहुंच गया है। संघर्ष शुरू होने के बाद भारत आने वाला यह पहला जहाज है, जो होर्मुज से होकर गुजरा है।

पुरी ने बताया कि वैकल्पिक खरीद के माध्यम से कमी की काफी हद तक भरपाई कर ली गई है। भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि 2006-07 में यह आंकड़ा 27 था। उन्होंने कहा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। हमारी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कभी-कभी तो 100 प्रतिशत से भी अधिक। विपक्षी सदस्यों ने इस बयान का विरोध करते हुए नारेबाजी की।

## केजरीवाल-मान ने गोल्डन टेंपल में मत्था टेका

**अमृतसर। ए।** शराब घोटाले मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुरुवार को श्री हरमंदिर साहिब (दरबार साहिब) में नतमस्तक हुए। इस दौरान केजरीवाल के परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने दरबार साहिब में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की और वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया।

## गूगल मैप्स अब एआई की मदद से सुझाएगा सटीक रास्ता

**न्यूयॉर्क।ए।** दिग्गज कंपनी गूगल ने बृहस्पतिवार को अपने डिजिटल मानचित्र मंच गूगल मैप्स में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि अब यह सेवा लोगों को कहीं जाने की योजना बनाने और वहां पहुंचने का बेहतर तरीका बताने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) का अधिक इस्तेमाल करेगी।

गूगल की जेमिनी प्रौद्योगिकी से संचालित इस बदलाव के तहत मैप्स में दो नई एआई आधारित सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक लोग इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। पहली सुविधा 'आस्क मैप्स' है, जो उपयोगकर्ताओं को बातचीत के अंदाज में सुझाव देगी। इसके जरिये उपयोगकर्ता मोबाइल चार्ज करने की नजदीकी जगह, कम भीड़ वाले कैफे या कई ठहराव वाली सड़क यात्रा के लिए विस्तृत यात्रा कार्यक्रम जैसी जानकारी पूछ सकेंगे। 'आस्क मैप्स' सुविधा शुरुआत में गूगल मैप्स के मोबाइल ऐप पर अमेरिका और भारत में आईफोन एवं एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसे बाद में कंप्यूटर और अन्य देशों में भी शुरू किया जाएगा।

**डिवाइडर भी दिखेंगे गूगल मैप में :** दूसरी नई सुविधा 'इमर्सिव नेविगेशन' है, जिसे गूगल ने मैप्स के ड्राइविंग निर्देशों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया है। यह सुविधा तीन-आयामी दृश्य के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को रास्ते की बेहतर समझ देगी। इसमें जेमिनी द्वारा तैयार 3डी दृश्य में प्रमुख इमारतें, सड़क के बीच बने डिवाइडर और आसपास का भू-भाग भी दिखेगा, जिससे वाहन चालकों को रास्ता समझने में आसानी होगी। यह सुविधा एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों के फायदे एवं नुकसान भी बताएगी। इसके अलावा गंतव्य पर पहुंचने के बाद पार्किंग के बेहतर स्थानों की जानकारी भी दे सकेगी। नई एआई-आधारित मार्गदर्शन सुविधा फिलहाल अमेरिका में गूगल मैप्स के मोबाइल ऐप और कारप्ले एवं एंड्रॉयड ऑटो से लैस वाहनों में उपलब्ध होगी।

# राष्ट्रपति मुर्मू ने टीएमसी सांसदों को नहीं दिया मिलने का समय

**ममता बनर्जी की पार्टी ने फिर लिखी चिट्ठी**

**नई दिल्ली। ए।** तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी पहल के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अवगत कराने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने 'समय की कमी' का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब शनिवार को राष्ट्रपति ने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि जब वह एक अंतरराष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बागडोगरा पहुंचीं तो न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही कोई मंत्री उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इस मामले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था।

**9 मार्च को तृणमूल ने लिखी थी राष्ट्रपति को चिट्ठी :** एक सूत्र के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नौ मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर सांसदों और राज्य के मंत्रियों सहित पार्टी के 12 से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिलने का समय मांगा था। पत्र में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में बताना चाहते हैं। हालांकि, इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति भवन ने तृणमूल कांग्रेस को पत्र भेजकर सूचित किया कि उनके अनुरोध पर विचार किया गया, लेकिन समय की कमी के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

# अय्यर और थरूर के बीच आरोप-प्रत्यारोप, लिखे पत्र

**अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच कांग्रेस पार्टी के दो नेता आमने-सामने**

**नई दिल्ली । ए।** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक खुला पत्र लिखकर पार्टी सांसद शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनसे किसी तरह का संबंध नहीं है, जिसको लेकर थरूर ने पलटवार किया कि अय्यर ने बहुत सारी अनावश्यक टिप्पणियां की हैं।

दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत उस वक्त हुई जब अय्यर द्वारा थरूर को एक खुला पत्र लिखा गया जो इस सप्ताह की शुरुआत में फेसबुक... कहा कि वह छह मार्च को एक टीवी चैनल पर इजराइल द्वारा अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ छेड़े गए अवैध युद्ध पर थरूर के सवालों के जवाब से काफी हैरान थे। अय्यर ने लिखा, मैं इतना परेशान हो गया हूं कि सो नहीं सका और सुबह तीन बजे उठकर आपको यह खुला पत्र लिख रहा हूं। अय्यर ने दावा किया कि उन्होंने न केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर को वोट देकर अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाया, जबकि उन्हें पता था कि थरूर बुरी तरह हारेंगे, बल्कि अगले दिन द इंडियन एक्सप्रेस में यह (आलेख) लिखकर भी कहा कि विजेता मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार और जी-23 समूह के कुछ लोगों के समर्थन के बावजूद उनके खिलाफ खड़े होने के (थरूर के) लोकतांत्रिक अधिकार का...

**अय्यर पर थरूर ने किया पलटवार**

अय्यर पर पलटवार करते हुए, थरूर ने एक खुला पत्र लिखा, जिसे एनडीटीवी ने बृहस्पतिवार को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि असहमति एक समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन किसी सहयोगी के इरादों या देशभक्ति पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाना उचित नहीं है कि वह विदेश नीति के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। थरूर ने कहा, हालांकि आप अपने विचार रखने के हकदार हैं, लेकिन मेरा रुख (और मेरे चरित्र) का आपका हालिया सार्वजनिक मूल्यांकन स्पष्ट प्रतिक्रिया की मांग करता है। थरूर ने कहा, मैंने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मामलों को स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखा है, भारत के हितों, सुरक्षा और वैश्विक स्थिति को हर चर्चा के केंद्र में रखा है। भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को पहचानना और भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति के लिए परिणामों का आकलन करना नैतिक आत्मसमर्पण नहीं है, यह जिम्मेदार शासनकला है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की कूटनीति ऐतिहासिक रूप से व्यावहारिकता...


**pnb | पंजाब नैशनल बैंक** सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)

**ई-नीलामी तिथि - 30/03/2026**
समयः सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

**सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री**
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की विक्रय "जहाँ है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

**सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची**

| क्र. | खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम | बंधक चल/अचल संपतियों का विवरण / मालिक का नाम | 1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति | आरक्षित मूल्य (लाख में) / ईएमडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपति के लिये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **उधारकर्ता: श्री एडविन फर्नांडीज, सह-उधारकर्ता: श्री लुईस फर्नांडीज,** पता - रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर 1, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001, **शाखा - सुंदर नगर, रायपुर (164010), संपर्क: श्री अजय पटेल, 9425017828** | **आवासीय मकान -** खसरा नं 597/2, 598/2 (भाग), पीसी नं 108/38, विनायक गार्डन, ब्लॉक 65, मौजा - शिवानंद नगर, सेक्टर 3, यतियातन वार्ड नं 4, **गोंदवारा,** रायपुर, छत्तीसगढ़ में **क्षेत्रफल- 800 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री एडविन फर्नांडीज पिता श्री लुइस फर्नांडीज। सीमाएं:- उत्तर: विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण: विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि. भौगोलिक निर्देशांक - 21.274860,81.625635 | 1) **07/08/2021** 2) **रू 15,13,400.04** + दिनांक 07-08-2021 से ब्याज प्रभावी 3) **10-01-22** को सांकेतिक कब्जा | **रू 15.81 लाख** / **रू 1.59 लाख** |
| 2 | **उधारकर्ता: 1) श्री सोहन दास मानिकपुरी** पिता श्री चरण दास मानिकपुरी **2) श्रीमती भारती मानिकपुरी** पति श्री सोहन दास मानिकपुरी, दोनों का पता: न्यू छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, ईडब्ल्यूएस-202, कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई, छ.ग, 490024. **शाखा कार्यालय: सेक्टर-6, भिलाई (096920) संपर्क: श्री दुबई हेम्ब्रोम 9340405787** | आवासीय मकान - मकान नं. ईडब्ल्यूएस 202, नगर निगम, भिलाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, मौजा: कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई, जिला: दुर्ग (छ.ग) में क्षेत्रफल- 40.50 वर्गमीटर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री सोहन दास मानिकपुरी पिता श्री चरणदास मानिकपुरी। सीमाएं :- उत्तर- ईडब्लूए-221, दक्षिण- सड़क, पूर्व-ईडब्लूएस-203 एवं पश्चिम - ईडब्लूएस-201। | 1) **22-08-2024** 2) **रू 4,32,816.00** + दिनांक 22-08-2024 से ब्याज प्रभावी 3) **28-10-24** को सांकेतिक कब्जा | **रू 7.44 लाख** / **रू 0.74 लाख** |
| 3 | **उधारकर्ताओं: श्रीमती पुष्पा राठौड़** पति श्री ललित राठौड़ एवं **श्री राहुल राठौड़** पिता श्री ललित राठौड़, दोनों का पता - पीएवी प्रोविजन स्टोर्स के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर -1, नीम बद्री, रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, खमतराई, रायपुर (छ.ग), 492001, **शाखा - सुन्दर नगर, रायपुर (164010) संपर्क: श्री अजय पटेल, 9425017828** | **आवासीय संपत्ति** - खसरा नं 435/15 (भाग), मौजा- खमतराई, प.ह नं 108/38, वार्ड नं 07, वीर शिवाजी वार्ड, सेक्टर-1, **शिवानंद नगर,** आर.आई.सी.- रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल- 1000 वर्ग फुट** पर स्थित अचल संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती पुष्पा राठौर पति श्री ललित राठौर। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य का मकान, पूर्व: देवांगन का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान। भौगोलिक निर्देशांक - 21.276278, 81.631752 | 1) **18.09.2021** 2) **रू 6,38,998.86** + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3) **18.04.22** को सांकेतिक कब्जा | **रू 22.46 लाख** / **रू 2.25 लाख** |

**संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समयः 27.03.2026 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं बयाना राशि जमा करने की तिथि व समयः 30.03.2026 दोप. 02:00 बजे तक**

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री दीनानाथ बागे, सीओ-एसएएम रायपुर, 9304614766

नोटः- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोटः- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी. 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को **ई-नीलामी दिनांक 30/03/2026 व समय सुबह 11.00 बजे** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री **ई-नीलामी दिनांक 30/03/2026 को सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें. इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Chronicle दिनांक 13.03.2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।